विकास पत्रिका

इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिसर्च एण्ड डवॅलपमेंट
(सहगल फाउंडेशन का प्रयास)

(अंक जनवरी – मार्च, 2008)

नवीनता एवं विकास की ओर...

पिछले अंक में हमने आपको सहगल फाउंडेशन के नए रूप – इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिसर्च एण्ड डवॅलपमेंट (इराद) से परिचित कराया था। फाउंडेशन अब इसी नये नाम से जाना जाएगा। इराद की नई इमारत गुड़गांव के सेक्टर 44 में बनकर तैयार है और कोर टीम अब नए भवन से कार्यरत है। इराद की समस्त कार्यवाहियां इसके तीन केन्द्रों से संचालित हैं: एकीकृत स्थायी ग्रामीण विकास मॉडल के अंतर्गत सभी प्रोग्राम इसके क्षमता विकास केन्द्र (Capacity Building Center) से लागू हो रहे हैं। दूसरे केन्द्र ग्रामीण शोध (Rural Research Center) में इच्छुक पी एच डी, फैलो व अन्य छात्रों को ग्रामीण समाज पर अध्ययन के अवसर प्रदान किये जाएगें। तीसरे केन्द्र नीति व शासन (Policy & Governance Center) में वर्तमान में लागू कानून, सरकारी नीतियां व कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी तथा ग्रामीण समुदाय को इस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इराद का एकमात्र उद्देश्य यह है कि विकास का अनुभव एक इन्स्टीट्यूट के द्वारा ग्रामीण संस्थाओं, ग्रामीण लोगों, कम्पनियों व सरकार तक पहुँचाया जा सके।

हम इराद के ज़रिये नीतिगत और परामर्श सम्बंधी मसलों पर सरकार के साथ मिलकर काम करते हुए ग्रामीण आबादी के विकास के लिए प्रयासरत रहेगें। हम आशा करते हैं कि आप सभी का सहयोग हमें अग्रणी ज्ञान संस्थान बनने में मददगार साबित होगा।

विकास पत्रिका के इस अंक में हम आपके लिए केन्द्रीय बजट 2008-2009 की सुर्खियां पेश कर रहें हैं। इस बजट में कृषि एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर अमल का वादा किया गया है। विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटन से ग्रामीण क्षेत्र के कायापलट की उम्मीद बढ़ती है।

उम्मीद है आप सभी पाठक इससे लाभान्वित होगें और विकास पत्रिका को सफल बनाने में अपना रचनात्मक सहयोग देते रहेगें।

ई–मेल: smsf@smsfoundation.org

असली शिक्षा

असंख्य अकादमिक विकल्पों और पाठ्यकमों के बावजूद मौजूदा समय में बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने में सफलता नहीं मिल रही है।

भारत की एक तिहाई आबादी 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है, और अगर हम देश का सर्वागीण विकास चाहते हैं तो शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है। मेवात में निम्न साक्षरता दर, लैंगिक असमानता और प्रजनन संबधी स्वास्थ्य जरूरतों व परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता के लिये इराद (सहगल फाउंडेशन) का लाईफ स्किल्स एजुकेशन(एलएसई) कार्यक्रम प्रयासरत है। यह युवाओं को ज्ञान और कुशलता से लैस करना चाहता है ताकि वे उचित फैसला लेने में सक्षम हों। यह नाबालिगों– खासकर किशोरियों– को अनौपचारिक शिक्षा मुहैया कराता है और सरकारी स्कूलों के साथ भी सहयोग करता है।

शिक्षा प्रणाली के उद्धार के लिए समाज के हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। इस आलेख में हम दो मामलों को उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए उन पर प्रकाश डालेंगे। एक मामले में सफलता मिल चुकी है जबकि दूसरा सफलता के दौर से गुजर रहा है। इन दोनों मामलों को पेश करने का एक मात्र उद्देश्य यह साबित करना है कि कैसे गंभीर प्रयासों से शिक्षा क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है।

सिरोली मॉडल स्कूल, मेवातः इस स्कूल ने मास्टर बसरुद्दीन के मार्गदर्शन में सफलता अर्जित की। मास्टर बसरुद्दीन 1995 में तब इस संस्थान से जुड़े थे जब इसमें महज 120 छात्र हुआ करते थे। उच्च क्वालिटी की शिक्षा मे विश्वास रखने वाले मास्टर जी कहते हैं, "बेहतर स्तर की शिक्षा उपलब्ध

मास्टर बसरूद्दीन (बाएं) को सम्मानित करते हुए क्षेत्रीय टीम के सदस्य

कराने में शिक्षक की भूमिका का खास महत्व है। अगर हर शिक्षक अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह निभाये तो क्रांति आ सकती है।"

अब यह स्कूल अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में तब्दील हो गया है। बदलाव की इस यात्रा में बसरूद्दीन को समुदाय का भरपूर साथ मिला। इस समर्थन के पीछे सिरोली मॉडल स्कूल को सफल बनाने में बसरूद्दीन द्वारा की गई कड़ी मेहनत और इस मिशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। अब इस स्कूल में 1400 छात्र हैं। पिछले साल 5000 छात्रों ने इस स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन किया।

मेवात में महिला साक्षरता दर की समस्या पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कूल में 350 लड़कियां हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य मे उनकी संख्या में और इज़ाफा होगा।

जाफराबाद प्राथमिक विद्यालय, तावडू (मेवात): जाफराबाद प्राथमिक विद्यालय सफलता का मुकाम हासिल करने की राह पर है। इराद (सहगल फाउंडेशन) के इस गांव में प्रवेश से पहले, शिक्षा की लचर व्यवस्था और शैक्षिक सुविधाएं चिंता का सबब थी। लेकिन कार्यक्रम के जरिए थोड़े हस्तक्षेप से ही क्षेत्र में दाखिला दर 70 फीसदी से बढ़कर 95 फीसदी हो गई और स्कूल में छात्रों की उपस्थिति 80 फीसदी से 98 फीसदी हो गई। इराद (सहगल फाउंडेशन) ने एक चारदीवारी, हैंड पंप और चार शौचालय बनवाकर मृतप्राय हो चुकी ग्रामीण शिक्षा समिति (वी.इ.सी.) के लिये क्षमता संवर्धन सत्रों का आयोजन कर इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। आज स्कूल समितियां रोज़ाना के मसलों पर मंथन करने और दाखिला दर बढ़ाने जैसी गतिविधियों में सक्रिय हैं। जाफराबाद प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापकगण शिक्षा प्रणाली में सुधार के मिशन पर लगे हुए

बैठक को संबोधित करते हुए अजीत सिंह

हैं। इनमें से जूनियर शिक्षक अजीत सिंह मास्टर बसरुद्दीन को अपना रोल मॉडल मानते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।

ग्रामीण शिक्षा समिति (वी.इ.सी.) की उभरती छवि की चर्चा हमने पत्रिका के पिछले अंक में की थी। वी.इ.सी. निरंतर अच्छा कार्य कर रही हैं।

वी.इ.सी. मीटिंग ब्योरा (मार्च 2008 तक)

नगीना		फिरोजपुर झिरका		तावडू	
गांव	कुल मीटिंग	गांव	कुल मीटिंग	गांव	कुल मीटिंग
करहेड़ा	16	अगोन	23	गोयला	30
उलेटा	9	रंगाला	18	डींगरहेड़ी	19
नौटकी*	18	रनियाला	17	जाफराबाद	15
सांठावाड़ी	9	पाठखोरी	7		
कोटला	6	भोंड	15		

* पिछले अंक में नौटकी वी.इ.सी. मीटिंग संख्या 2 दिखाई गई थी। हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं।

सांठावाडी में मनाया गया खेत दिवस

इराद (सहगल फाउंडेशन) द्वारा कृषि विकास में किए जा रहे प्रयासों और किसान मित्रों की लगन के चलते कई किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ग्राम सांठावाडी में नौ एकड़ जमीन पर लगी सौंफ की फसल की पैदावार बहुत अच्छी रही। इराद (सहगल फाउंडेशन) ने यह बीज कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से किसानों को उपलब्ध कराया।

27 फरवरी 2008 को कृषि विज्ञान केंद्र ने इराद के

उच्च चरित्र इन्सान की सर्वश्रेष्ठ सम्पति है।

साथ मिलकर गांव सांठावाडी में खेत दिवस मनाया। खेत दिवस, कृषि विज्ञान केंद्र का एक प्रयास है जिसमें कृषि अधिकारी खेतों का दौरा करते हैं और किसानों को फसल व उपज के बारे में समझाते हैं।

केंद्र के वैज्ञानिक एवं इराद (सहगल फाउंडेशन) से आय वृद्धि एवं संचार भाग संभाल रहे लोगों ने खेतों का दौरा किया। सुभान खान के खेत के एक एकड़ हिस्से में लगी सौंफ की फसल को खासा सराहा गया। सुभान खान ने इस फसल को टमाटर के साथ इंटरक्रापिंग में लगाया। पूछने पर सुभान खान ने बताया कि टमाटर की खेती से तकरीबन 30,000 रुपये की आमदनी हो गई है। एक एकड़ में उसे लगभग 100 किलो सौंफ की उपज का अंदाजा है जो अतिरिक्त फायदा देगी।

कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यकर्ताओं ने खेत दिवस के अवसर पर कहा कि यदि किसान उत्साह दिखाए तो वे सरकारी बीज व तकनीक उन्हें निशुल्क उपलब्ध करवा सकते हैं। इराद (सहगल फाउंडेशन) का हमेशा यही प्रयास है कि किसानों के उत्पादन में वृद्धि हो।

कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. चौहान एवं एम.ए. खान ने इराद को धन्यवाद देते हुए मेवात के किसानों की मदद करने का भरोसा दिया। उन्होंने आने वाले दिनों में किसानों को ट्रेनिंग देने का सुझाव भी दिया।

पशुपालन की प्राथमिकता

पशुपालन कृषि से जुड़ा एक प्रमुख हिस्सा है। इराद (सहगल फाउंडेशन) ने कृषि एवं किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु कई प्रयत्न किए हैं। 21 जनवरी, 2008 को गांव कोटला में किसानों के साथ हुए पशुपालन प्रशिक्षण का परिणाम काफी सकारात्मक रहा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन पशुधन प्रशिक्षक, डा. नसीम अहमद ने किया। डा. अहमद ने पशुओं के बारे में किसानों को जानकारी देते हुए पशुधन से आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की।

डा. अहमद ने कुछ किसानों को उनके पशुओं के लिए संतुलित आहार दिया। पांच किसानों की बकरियों एवं बकरों को यह आहार दिया गया। 15 दिनों के बाद सर्वेक्षण में पाया गया कि इस आहार से पशुधन के वजन और दूध की मात्रा में काफी वृद्धि हुई। यह आहार 15 दिन बाद एक बार फिर दिया गया।

इस प्रशिक्षण के बाद 5 किसानों को हुए फायदे का ब्योरा–

किसान (पशु)	पौष्टिक आहार देने से पहले की दूध की मात्रा	पौष्टिक आहार देने से पहले का वजन	15 दिन बाद दूध	15 दिन बाद वजन	एक महीने बाद दूध	एक महीने बाद वजन
जकरिया (बकरा)	–	14 किलो ग्राम	–	17 किलो ग्राम	–	17.5 किलो ग्राम
मेमराज (बकरी)	1.5 लीटर	16 किलो ग्राम	2 लीटर	17 किलो ग्राम	2.5 लीटर	17.5 किलो ग्राम
सुरजन (बकरा)	–	15 किलो ग्राम	–	17.5 किलो ग्राम	–	18.5 किलो ग्राम
इमामुदीन (बकरी)	1 लीटर	17 किलो ग्राम	3 लीटर	18.5 किलो ग्राम	3 लीटर	19 किलो ग्राम

इस असर को देखने के बाद किसानों ने पशुधन के पौष्टिक आहार जारी रखने की इच्छा जाहिर की और यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो किसान अपनी आजीविका हेतु केवल पशुधन आय पर निर्भर करते हैं, अगर वे अपने पशुओं को निरन्तर पौष्टिक आहार दें तो उनकी पशुधन आय में 15% से 20% तक की वृद्धि हो सकती है।

निर्मल गांव बनने से कुछ ही कदम दूर

तावडू खण्ड के गांव गोयला, डींगरहेडी, जाफराबाद व डालाबास में निजी–शौचालय के इस्तेमाल की प्रक्रिया लोकप्रिय हो रही है। इराद (सहगल फाउंडेशन) के तत्वाधन में आयोजित रैली एवं स्वच्छता अभियान के तहत घर–घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया जिसकी बदौलत गांवों में प्रतिदिन एक शौचालय बनाने का सपना साकार हुआ।

जनवरी 2008 में 33 शौचालय बने और मात्र चार माह में 87 निजी शौचालय बनाए गए जो कि मेवात क्षेत्र में मिसाल बन गई है। आज चार गांवों में 332 निजी शौचालय हैं। गौरतलब यह है कि इराद (सहगल फाउंडेशन) के जाने से पहले तावडू खण्ड के इन्हीं चार गांवों में केवल 27 शौचालय थे। गांव के जिम्मेदार और जागरूक लोग यहां सौ प्रतिशत शौचालय एवं सोकपिट का निर्माण देखना चाहते हैं। गांववासी अब मानते हैं कि गांव में सफाई रहने से विभिन्न बीमारियां पांव नहीं पसार सकती। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में प्रतिदिन एक निजी शौचालय बनना छोटी बात नहीं है। इस सब का श्रेय इराद (सहगल फाउंडेशन) की टीम को जाता है।

इस खण्ड में जितने शौचालय बने हैं वह कम खर्चे में बनवाए गए हैं। कम खर्च के शौचालय बनाने में इराद (सहगल फाउंडेशन) की भूमिका–

(1) पिट खोदने की तकनीक मुहैया करवाना

(2) एक शौचालय बनाने पर 1000 रुपये का अनुदान

(3) शौचालय बनाने के लिए लोगों में जागरूकता रैली

(4) किस जमीन पर कच्चे गड्ढे वाली तकनीक चल सकती है, इस संबंध में तकनीकी सलाह और मदद

टीकाकरण जरूरी

इराद (सहगल फाउंडेशन) के जाफराबाद में जाने से पहले, 0–5 साल के बीच के दो बच्चों की टीका पकने से मौत हो गई थी जिसके चलते लोगों ने टीकाकरण करवाना बंद कर दिया। यह देखते हुए इराद (सहगल फाउंडेशन) ने घर–घर जाकर टीकाकरण के फायदे बताए और महिलाओं को जागरूक करने के लिए अलग से इस विषय पर चर्चा सत्र आयोजित किए।

एएनएम ने भी स्वास्थ्य केंद्र पर पूरा समय दिया। इससे लोगों में टीकाकरण से जुड़ा भय कम हुआ और मां–बाप ने अपने बच्चों का टीकाकरण करवाया। इन्हीं सकारात्मक कोशिशों से पूरे गांव के बच्चों का टीकाकरण हुआ और यह जारी है।

अब नौटकी के लोग खुले में शौच नहीं करेंगे

इस धरती पर मानव के उदगम से लेकर आज तक सब कुछ बदल गया लेकिन एक चीज नहीं बदली। मानव अपनी आदिम अवस्था में खुले में शौच जाता था। भारत में अधिकांश लोग आज भी ऐसा करते हैं। देश के 30% घरों मे शौचालय बने हुए है लेकिन सिर्फ 15% लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अर्थात 85% लोग आज भी खुले में शौच जाते हैं। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे समाज में 80% बिमारियां खुले में शौच जाने की प्रवृति की वजह से होती है।

लेकिन क्या शौचालय बनाना इस समस्या का हल है? आजादी के बाद घरों में शौचालय बनाने के नाम पर जितना पैसा बहाया गया उतने से आज तक देश के हर घर में दो शौचालय और एक स्वीमिंगपूल बन गए

होते। सवाल उठता है कि ऐसी स्थिती में क्या किया जाए। ऐसा माना जाता है कि सामाजिक परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है। लेकिन क्या यह अनन्त प्रक्रिया है? क्या आदमी विशेषकर हमारे देश में खुले में मल त्याग करना कभी बंद नहीं करेगा? सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। मानव मस्तिष्क को झंकझोरने की एक नई पद्दति विकसित हुई है जिसके तहत व्यक्ति खुले में मल त्यागने के अपने व्यव्हार के प्रति घृणा व शर्म महसूस करता है व तुरन्त प्रभाव से अपना उक्त व्यवहार बदल लेता है।

26 फरवरी के दिन इराद (सहगल फाउंडेशन) की टीम नौटकी गांव के लोगों को गांव के बीच एक ऐसी जगह ले गई जहां ताजा मानव मल प्रचुर मात्रा में बिखरा पड़ा था । भीड़ मल के चारों तरफ इक्कठी की गई। इसमें औरतें, आदमी, बच्चे बूढे सभी शमिल थे। टीम द्वारा टट्टी के विशलेषण से उपस्थित लोगों के मन पर जैसे बिजली कौंधि। उन्होंने महसूस किया कि खुले में मल त्यागने की वजह से वे न केवल अपना मल दूसरों को खिला रहें हैं बल्कि वे खुद भी अपना व दूसरों का मल खा रहे हैं – प्रतिदिन, प्रतिपल।

इराद (सहगल फाउंडेशन) टीम के गांव से चले जाने के बाद गांव के लोंगों ने इस पर चर्चा की। आपसी मंथन के बाद सरपंच की अध्यक्षता मे गांव के लोगों ने गांव के हर घर में शौचालय बनाने का निर्णय किया। समाचार लिखे जाने तक गांव मे 17 शौचालय बन चुके हैं। अनुमान है कि अप्रैल माह के अंत तक 'नौटकी' के हर घर मे शौचालय बन जाएगा। उसके बाद वह समय आएगा जिसमें इस गांव का कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाएगा। हो सकता है नौटकी ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला मेवात जिले का पहला गांव हो।

व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

भारत में 25 वर्ष से कम लोगों की आबादी 55 करोड़ से अधिक है, लेकिन लाभकारी नौकरियों के लिए जरूरी दक्षता से पूरी तरह लैस नहीं होने के कारण युवाओं में बेरोज़गारी की दर ऊंची है। मौजूदा शिक्षा प्रणाली उच्च प्रशिक्षित लोगों की रोजगार क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरी करने में सफल नहीं है और इसलिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की जरूरत बढ़ती जा रही है।

इराद (सहगल फाउंडेशन) के कम्पयूटर एवं विद्युतकर्मी प्रशिक्षण की अच्छी सफलता के बाद, तावरू प्रखंड के गोयला समुदायिक केन्द्र में 14 मार्च से मोबाइल मरम्मत कोर्स शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को इस तकनीकी के मामले में हुनरमंद बनाना और उन्हें रोजगार हासिल कराने या अपना लघु उद्यम शुरू करने में मदद देना है।

कोर्स के लाभकारी संचालन के लिये इराद की टीम ने ने एक गुणी प्रशिक्षक की पहचान कर ली है जो मोबाइल की मरम्मत करने के गुर से वाकिफ है। मोबाइल मरम्मत कोर्स की अवधि तीन महीने की होगी। हर सप्ताहांत में सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक दो बैच चलाए जाएंगे। इन दो बैचों में 30 छात्रों का दाखिला किया गया है।

हम उम्मीद करते हैं कि यह परियोजना ग्रामीण युवाओं में रोजगार दर बढ़ाने और उन्हें लाभान्वित करने में सफल होगी।

न रिष्येम कदाचन । अनीति के आगे सिर न झुकाओ।

बजट 2008–2009: एक नज़र

आम तौर पर संसद में वित्त मंत्री जब वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हैं तब देश में इस पर तमाम चर्चायें होती हैं। विभिन्न वर्ग अपने हित और अनहित के दृष्टिकोण से बजट के प्रावधानों का मूल्यांकन करते हैं। यह लोकतंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बजट पर होने वाली चर्चाओं में अधिकतर व्यापार व उद्योग जगत से संबंधित लोगों की भागीदारी ही प्रबल रूप में दिखाई देती है। किसान व आम आदमी इन चर्चाओं में कोई असरकारक भूमिका नहीं निभा पाता। बजट के प्रावधानों की सही जानकारी का अभाव इस स्थिति का एक प्रमुख कारण है। विकास पत्रिका के इस अंक में बजट 2008–2009 के कुछ प्रमुख प्रावधान इस आशय के साथ दिये जा रहे हैं कि किसान व आम आदमी इन्हें जान सके और इन पर होने वाली चर्चाओं से अनभिज्ञ न रहे। साथ ही आवश्यक यह भी है कि बजट के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में वह अपनी क्रियाशील भूमिका निभा सके।

अर्थव्यवस्था :

• पिछले तीन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की दर 8.8 प्रतिशत।

• वर्ष 2007–2008 में कृषि वृद्धि दर अनुमानतः 2.6 प्रतिशत।

• वर्ष 2007–2008 में 2193.2 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान– जो अब तक का रिकॉर्ड है। इसमें 940.8 लाख टन चावल, 167.8 लाख टन मक्का, 94.5 लाख टन सोयाबीन व 233.8 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ है। यह भी एक रिकॉर्ड है।

भारत निर्माण (ग्रामीण ढांचे के लिए चार वर्षीय योजना) :

• बजट 2008–2009 में इस योजना के लिए 31,280 करोड़ रूपये का प्रावधान।

सर्वशिक्षा अभियान :

• 13,100 करोड़ रूपये का प्रावधान। मध्याह्न भोजन योजना के लिए 8000 करोड़ रूपये का प्रावधान। माध्यमिक शिक्षा के लिए 4554 करोड़ रूपये का प्रावधान।

जवाहर नवोदय विद्यालय :

• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बहुलता वाले 20 जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए 130 करोड़ रूपये।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय :

• शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 410 नये विद्यालयों के लिए धन की व्यवस्था (सर्व शिक्षा अभियान की निधि से। साथ ही बालिका विद्यालयों से संबद्ध छात्रावासों के उन्नयन अथवा नये छात्रावासों को खोलने के लिए 80 करोड़ रूपये का प्रावधान।

राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति :

• चार वर्ष में 3000 करोड़ रुपये की आधारभूत निधि का निर्माण करने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान। इसके तहत 2008–2009 से क्रियान्वित करके 1,00,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी।

नेहरू युवा केंद्र :

• 123 जिलों में केंद्र स्थापित करने व पहले वर्ष में आवर्ती व्यय पूरा करने के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान।

स्वास्थ्य :

• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 16,534 करोड़ रुपये का प्रावधान–पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) :

• 12,050 करोड़ रूपये का प्रावधान।

एच. आई. वी./ एड्स :

• राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 993 करोड़ रूपये का प्रावधान।

पोलियों :

• 1,042 करोड़ रूपये का प्रावधान।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना :

• असंगठित क्षेत्र के बी. पी. एल श्रेणी के कामगारों व उनके परिवार के सदस्यों को 30,000 रूपये का स्वास्थ्य कवर देने की योजना। यह योजना दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान राज्यों में 1 अप्रैल, 2008 से प्रारंभ की जाएगी। केंद्र के हिस्से के प्रीमियम के तौर पर 205 करोड़ रूपये का प्रावधान।

राष्ट्रीय वृद्धजन योजना :

• राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम 2008–2009 में 400 करोड़ रूपये के आयोजना परिव्यय के साथ आरंभ किया जाएगा।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) :

• आई सी डी एस के लिए 6300 करोड़ रूपये का प्रावधान।

• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मेहनताना 1000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रतिमाह किया गया।

• आंगनवाड़ी साहिकाओं का मेहनताना 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 750 रूपये प्रतिमाह किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना :

• भारत के सभी 596 ग्रामीण जिलों में यह योजना 16,000 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ शुरू की जाएगी। मांग होने पर अधिक धन उपलब्ध कराया जाएगा।

राजीव गांधी पेयजल मिशन :

• 7,300 करोड़ रूपये का प्रावधान।

पूर्ण स्वच्छता अभियान :

• 1,200 करोड़ रूपये का प्रावधान।

छात्रवृत्तियां :

अनुसचित जाति – 1,200 करोड़ रूपये का प्रावधान। अनुसूचित जनजाति – 195 करोड़ रूपये का प्रावधान। अन्य पिछड़े वर्ग – 164 करोड़ रूपये का प्रावधान। अल्पसंख्यक (मैट्रिकोत्तर) – 100 करोड़ रूपये का प्रावधान।

महिला एवं बाल विकास :

• शत प्रतिशत महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 11,460 करोड़ रूपये का प्रावधान।

• 16,202 करोड़ रूपये का प्रावधान ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिनमें 30 प्रतिशत हिस्सा महिला विशिष्ट कार्यक्रम के लिए।

महिला स्व–सहायता समूह :

• भारतीय जीवन बीमा निगम से "जनश्री बीमा योजना" का विस्तार कर सभी महिला सहायता समूहों, जो बैंकों की ऋण व्यवस्था से जुड़े हैं, को शामिल करने के लिए कहा गया है।

कृषि ऋण :

• वर्ष 2008–2009 के लिये कृषि ऋण हेतु निर्धारित राशि 280,000 करोड़ रुपये। ब्याज सहायता के लिये 1600 करोड़ रूपये का प्रारंभिक प्रावधान।

कृषि में निवेश : कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में समग्र पूंजी निर्माण (जीसीएफ) 2003–04 में 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 2006–07 में 12.5 प्रतिशत हो गया। इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4 प्रतिशत वृद्धि दर की प्राप्ति के लिये 16 प्रतिशत किया जाएगा।

जल संसाधन :

• त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) : 24 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा 753 छोटी सिंचाई योजनाएं 2007–08 में पूरी की जाएंगी जिससे 500,000 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। इसके लिये 2007–08 में 11,000 करोड़ रूपये के परिव्यय को बढ़ाकर 2008–09 में 20,000 करोड़ रुपये किया गया।

वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम को अंतिम रुप दे दिया गया है और इसे 348 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ 2008–2009 में प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अभी तक जल संभरण विकास योजनाओं के लाभार्थी नहीं रहे हैं।

• सूक्ष्म सिंचाई संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना:

इस योजना के तहत 400,000 हैक्टेयर भूमि को शामिल करने के लक्ष्य के साथ 500 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया।

जल निकाय :

• जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली की परियोजना के अन्तर्गत तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने विश्व बैंक के साथ 7380 लाख अमरीकी डालर की कुल राशि के समझौते किये। इसी प्रकार के समझौते विश्व बैंक और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा अन्य कुछ राज्यों के साथ किये जाएंगे।

सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम :

• सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के रुप में 14 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई। दीर्घकाल तक चलने वाली बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निधिपोषण के लिए 100 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी से "सिंचाई तथा जल संसाधन" वित्त निगम के गठन का प्रस्ताव।

• राष्ट्रीय बागवानी मिशनः इस मिशन के तहत 18 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें हरियाणा राज्य शामिल है, के 340 जिलों के लिये 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान।

मृदा परीक्षण :

• सरकार की 30 लाख रुपये प्रति प्रयोगशाला को सहायता प्रदान करने के साथ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की जाएंगी। कृषि मंत्रालय को 75 करोड़ रुपये का एक बारगी आवंटन किया जा रहा है ताकि देश के 250 जिलों में एक–एक पूर्णतया सज्जित चलती–फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाए।

बागवानी फसलें :

• पुनः रोपण और नवीकरण के लिए गठित विशेष प्रयोजन चाय निधि के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• चाय, रबर, तम्बाकू, मिर्च, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और इलायची के लिये फसल बीमा योजना प्रारंभ की जाएगी। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन कर इसे एक स्वयात्व राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

• फसल बीमा : खरीफ व रबी फसल के लिये राष्ट्रीय फसल बीमा योजना अपने मौजूदा स्वरूप में

महान व्यक्ति का मुख्य लक्षण उसकी नम्रता है।

लागू रहेगी। इस योजना के लिये 644 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• मौसम आधारित फसल बीमा योजना : पांच राज्यों, जिसमें हरियाणा शामिल है, के चुनिंदा क्षेत्रों में प्रायोगिक योजना के रूप में कार्यान्वित यह योजना जारी रहेगी। इसके लिये 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।

उर्वरकों के लिए सब्सिडी :

• किसानों के लिये उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी।

सहकारी ऋण संरचना :

अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन संबंधी प्रोफेसर वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट 17 राज्यों, जिनमें हरियाणा भी शामिल है, में क्रियान्वित की जा रही है। अब तक केंद्र सरकार द्वारा चार राज्यों को 1,185 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन संबंधी रिपोर्ट को कियान्वित करने के पैकेज की सहमति संबंधी एक समझौते पर पहुंच गये हैं। इस योजना में केंद्र सरकार का हिस्सा कुल भार का 2,642 करोड़ रुपये अथवा 86 प्रतिशत होगा।

किसानों के लिये ऋण माफी और ऋण राहत : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा 31 मार्च, 2007 तक संवितरित सभी ऋण और 31 दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।

• सीमांत और छोटे किसानों के लिये उन सभी ऋणों की पूर्ण माफी होगी जो 31 दिसंबर 2007 को अतिदेय हो गये थे और जो 29 फरवरी, 2008 तक चुकता नहीं किये गये।

• अन्य किसानों के संबंध में सभी ऋणों के लिए एक बारगी निपटान योजना होगी। ऐसे किसान जिन पर 31 दिसम्बर, 2007 तक ऋण अतिदेय रहा और 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहा, वे एक बारगी निपटान के अंतर्गत 75 प्रतिशत शेष के भुगतान के एवज में 25 प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकेंगे।

• वर्ष 2004 और 2006 में विशेष पैकेजों के माध्यम से पुनर्संचित और पुनर्निर्धारित कृषि ऋण या तो माफी अथवा उपर्युक्त पद्धति के आधार पर एक बारगी निपटान के पात्र होंगे।

• इस योजना से लगभग 3 करोड़ छोटे व सीमांत किसान तथा लगभग 1 करोड अन्य किसान लाभान्वित होंगे। माफ किये जा रहे अतिदेय ऋणों का कुल मूल्य 50,000 करोड़ रुपये अनुमानित है तथा एक बारगी निपटान पर छूट का मूल्य 10,000 करोड़ रुपये अनुमानित है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि :

• ग्रामीण सड़कों के लिये एक अलग प्रयोजन के साथ ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के लिए 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना :

• 28,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान यह योजना जारी रहेगी। 2008–09 में इसके लिये 5,500 करोड़ रुपये का आबंटन।

हथकरघा क्षेत्र :

• 250 समूहों का विकास किया जा रहा है और हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिये सामूहिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत 443 यार्न बैंकों की स्थापना की गई है। मार्च 2008 तक 17 लाख से अधिक बुनकर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम :

• भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक (सिडबी) में जोखिम पूंजी निधि का सृजन किया जा रहा है। 31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार सिडबी के साथ ऋण गारण्टी न्यास ने 2,479 करोड़ रुपये की राशि के लिये 89,129 यूनिटों को गारण्टी प्रदान की। सिडबी गारण्टी शुल्क 1.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत और 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिये वार्षिक सेवा शुल्क 0.75 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करेगा।

वित्तीय क्षेत्र

वित्तीय समावेशन :

• वित्तीय समावेशन संबंधी समिति की वह सिफारिश स्वीकार किये जाने के लिये प्रस्तावित जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध–शहरी शाखा ने प्रतिवर्ष कम से कम 250 ग्रामीण परिवारों को खाता खोलने की सलाह देनी होगी।

• सरकार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा स्थापित उदाहरणों को अपनाने व स्व–सहायता समूह के सदस्यों की सभी ऋण संबंधी आवश्यकताओं जैसे आय उपार्जक क्रियाकलाप, सामाजिक आवश्यकताओं जैसे आवास, शिक्षा, विवाह आदि और ऋण अदला–बदली की आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध करेंगी।

• नाबार्ड में 5000 करोड़ रुपये की निधि के सृजन का प्रयोजन ताकि उससे अल्पावधिक सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनर्वित्तपोषण कार्य में बढ़ोतरी हो।

• सिडबी में 2000 करोड़ रुपये की दो निधियों के सृजन का प्रावधान जिनमें से एक जोखिम पूंजी वित्त पोषण और दूसरी एमएसएमई की पुनर्वित्तपोषण क्षमता बढ़ाने के लिये।

• ग्रामीण आवास क्षेत्र में पुनर्वित्तपोषण कार्य बढ़ाने के लिये एनएचबी में 1200 करोड़ रुपये की निधि का सृजन।

• लाभ प्रद व्यवसायों में लगे हुए कमजोर वर्गों के लिये डीआरई स्कीम के तहत ऋण की उधारकर्ता की पात्रता मानदण्ड में बढ़ोत्तरी।

अन्य प्रस्ताव :

• कौशल विकास मिशन : बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिये अपेक्षित कौशल की चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक गैर–लाभकारी निगम की स्थापना का प्रावधान। इसके लिये सरकारों, सरकारी और निजी क्षेत्र व द्विपक्षीय स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये एकत्र किये जाएगें। इस गैर–लाभकारी निगम में सरकार की इक्विटी 1,000 करोड़ रुपये की होगी।

• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान : विश्व बैंक की सहायता से 238 आईटीआई का उन्नयन किया जा रहा है। 300 अन्य आईटीआई का उन्नयन करने की प्रत्याशा में 750 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली : पीडीएस व अन्य कल्याण कार्यक्रमों के तहत खाद्य सब्सिडी के लिये 32,667 करोड़ रुपये का प्रावधान। हरियाणा राज्य व चंडीगढ़ संघ राज्य में प्रायोगिक आधार पर स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण प्रणाली द्वारा पीडीएस के तहत खाद्यान्न वितरण का कार्य आरंभ किया जाएगा।

असंगठित क्षेत्र के कामगार :

असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधेयक 2007 के कानून बनाए जाने की प्रत्याशा में असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए चरणबद्ध तरीके से योजनाएं आरंभ की गई हैं।

(1) गरीब परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना चलाई गयी है। इस योजना के प्रथम वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम 30 सितम्बर, 2008 तक एक करोड़ भूमिहीन परिवारों को शमिल करेगा। 1500 करोड़ रुपये एलआईसी के पास रखे गए हैं, वर्ष 2008–09 में 1,000 करोड़ रुपये और एलआईसी के पास रखे जायेंगे ताकि योजना के दूसरे वर्ष में 1 करोड़ और गरीब परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाये।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरम्भ 1 अप्रैल 2008 से किया जायेगा।

(3) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम 11 नवम्बर, 2007 से विस्तारित की गई है ताकि इसमें बीपीएल श्रेणी के 65 वर्ष से अधिक सभी व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। इस योजना के तहत मौजूदा 87 लाख लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 157 लाख किया जायेगा। इसके लिए 2008–09 में 3,443 करोड़ रुपये का प्रावधान।

गरीबों के लिए आवास

इन्दिरा आवास योजना के तहत 60 लाख मकानों के लक्ष्य की तुलना में 41.13 लाख मकानों का निर्माण किया गया। मार्च 2008 तक इस योजना के तहत बनाये गये कुल मकानों की संख्या 51.77 लाख होगी। 1 अप्रैल 2008 से मैदानी इलाकों में स्वीकृत मकानों पर सब्सिडी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये की गयी जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वीकृत मकानों के लिए यह राशि 27,500 रुपये से बढ़ाकर 38,500 रुपये की गयी। इसी तरह मकानों के उन्नयन के लिए सब्सिडी की राशि को 12,500 रुपये प्रति मकान से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति मकान किया गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ब्याज की विभेदक दर योजना के तहत इंदिरा आवास योजना को शामिल करने और 4 प्रतिशत की दर से प्रति मकान 20,000 रुपये का कर्ज देने का सुझाव दिया गया है।

जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज)

इस विषय पर विचारों के अन्वेषण तथा कार्यान्वयन में विकासात्मक व समन्वयकारी भूमिका निभाने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की जायेगी।

(स्रोतः वित्त मंत्रालय, भारत सरकार)

छोटी बात–बड़ी बात

(1) देशभर में गणतंत्र दिवस बहुत ही धूम–धाम से मनाया जाता है। इराद (सहगल फाउंडेशन) की मदद से यह दिवस इस बार 11 गांवों में मनाया गया। इनमें से 8 गांवों में यह दिवस पहली बार मनाया गया। फिरोजपुर झिरका ब्लॉक के पाठखोरी प्राइमरी स्कूल में यह दिवस बडे ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस असर पर स्कूल के प्रमुख अध्यापक, गांव के पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के चेयरमैन शामिल हुए। इस रंगारंग कार्यक्रम में लड़कियों ने भारी संख्या में भाग लिया।

(2) इराद (सहगल फाउंडेशन) द्वारा करहेड़ा प्राइमरी स्कूल में नियुक्त की गई अध्यापिका, श्रीमती ललिता सैनी के आने से बच्चों की औसत उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है। स्कूल में आ रही लड़कियों की संख्या 74 से बढ़कर 111 हो गई है।

(3) इराद की फील्ड टीम ने फरवरी में मेवात में हुए पांच दिवसीय भारत निर्माण अभियान में भाग लिया। इससे पहले यह अभियान हरियाणा के सिरसा, महेन्द्रगढ़ एवं अंबाला में आयोजित हो चुका है। इस अभियान के दौरान सभी ग्रामीणों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान एवं अन्य सरकारी नीतियों से रुबरू कराया गया।

(4) स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु, इराद (सहगल फाउंडेशन) ने नगीना एवं फिरोजपुर झिरका ब्लाक के स्कूलों के पांचवीं एवं आठवीं कक्षा के बच्चों में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करना था। प्रतियोगिता के अंत में विजेता छात्रों को शब्दकोष इनाम में दिये गए।

दूसरों के साथ वह व्यहवार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं।